अरुणाचल भारत का है और रहेगा

नक्शा बदलने से सच्चाई नहीं बदलेगी

हरिभूमि ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा तथा चीनी नक्शों में इस राज्य को उस देश का दिखाए जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेण्टस यूनियन के अध्यक्ष तकाम ततुंग ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आप्सू प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही है। ततुंग ने सिंह के हवाले से कहा कि अरुणाचल हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। चीन द्वारा अरुणाचल के लोगों को 'नत्थी वीजा' जारी करने के बारे में सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार इस समस्या के जल्द समाधान के लिए हरसंभव उपाय कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल को अलग-थलग नहीं रखा जा सकता और विकास के फायदे देश के अन्य हिस्सों की तरह उसे भी पहुंचने चाहिए। ततुंग के मुताबिक प्रधानमंत्री ने 2008 की अपनी अरुणाचल यात्रा का

जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाना चाहिए और केन्द्र तथा राज्य की सरकारें विकास की गति तेज करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। आप्सू प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के संज्ञान में दशकों पुराने चकमा-हजोंग, तिरप और चांगलांग में उग्रवाद, असम-अरुणाचल सीमा विवाद जैसे मुद्दे रखे। जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा औद्योगिक देशों को उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को पाने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए जिससे कोपेनहेगन सम्मेलन में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। सिंह ने कहा कि भारत, चीन और कई अन्य विकासशील देशों ने प्रदूषण उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य और विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं।

पर्यावरण मानदंड लागू करें

हरिभूमि ब्यूरो

पीएम की जयराम को नसीहत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल प्रगति की वकालत करते हुए पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को ज्यादा कानूनबाजी न दिखाने की नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए उचित नियामक मानदंड लागू करने के साथ लाइसेंस राज खत्म करने पर भी बल दिया।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आयोजित दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक 2011 के उद्घाटन के मौके पर टेरी सम्मेलन में कहा कि पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए उचित नियामक मानदंडों का उल्लंघन करके प्रदूषण फैलाने वालों से कीमत वसूलने का सिद्धान्त भी लागू किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कीमत पर लाइसेंस परिमिट राज न लौट पाये। उन्होंने कहा कि देश लाइसेंस परमिट राज से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकला है, लेकिन पर्यावरण मंत्री के ज्यादा नियम कानून के चक्कर में कहीं लाइसेंस राज वापस न लौट जाए। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई और पॉस्को जैसे प्रोजेक्ट को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुके जयराम रमेश पर पीएम का यह बयान निश्चित ही विचारणीय है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जयराम को नसीहत से एक तरफ जहां पर्यावरण मंत्री को अपनी नीतियों पर ध्यान देने की ओर इशारा किया गया तो दूसरी ओर देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को विकास पर आगे बढ़ाने की वकालत भी की गई। उन्होंने कहा कि वह इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि मानदंड बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना जरूरी है जो अक्सर मुश्किल होता है। किसी भी सतत विकास को सुनिश्चित करने की रणनीति का केंद्रीय सिद्धात यह है कि आर्थिक पहलुओं का फैसला करने वाले सभी लोगों या संगठनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे पर्यावरण अनुकूल बातों को हमेशा ध्यान में रखें।